SCH-DC/4.00/2H

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : कैसे आप देश की तरक्की कर सकते हैं? एक तरफ चीन आपकी सीमा पर कब्जा कर रहा है, आपके व्यापार पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों को रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं। पिछले वर्ष आपने जो बजट रखा था, उसके मुताबिक रोज़गार में आपको कम से कम 20% से 30% की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, तब हम मानते कि आपने बजट के कार्यान्यवन की उचित व्यवस्था की है।

मान्यवर, हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अमरीका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में, जहां केवल 8% लोग खेती करते हैं, वहां की सरकार किसान को सारी सहूलियतें देती है और उनकी उत्पादन लागत, उनका नफा और बाकी सब खर्च लगाकर उनके उत्पाद का समर्थन मूल्य तय करती है और फिर उनके सारे उत्पाद को खरीदने का काम भी सरकार ही करती है। हमारे यहां क्या व्यवस्था है? हमारे यहां किसान मर रहा है, घाटे की खेती कर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। इस समय लोग मटर, आलू, टमाटर इत्यादि को मुफ्त बांट रहे हैं कि भैया, आओ और खेत से उठा कर ले जाओ। उनकी लागत तक उन्हें वापस नहीं मिल रही है। आपके बजट और नोटबंदी का यह प्रभाव पड़ा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है।

मान्यवर, हमारा देश 'सोने की चिड़िया' कहलाता था। दशहरे के मौके पर पहले गांव-गांव में लोग कबड्डी और कुश्ती लड़ा करते थे, लेकिन आज खेल हमारे देश से पलायन कर रहे हैं। जितने भी ओलम्पिक खेल हो रहे हैं, वहां हमारे खिलाड़ी भी जा रहे हैं, लेकिन आप कितने गोल्ड मैडल लेकर आ रहे हैं? तीन साल में आप कितने गोल्ड मैडल लाए हैं, बताइए? अगर एक भी लाए हों, तो बता दीजिए। आपने उन खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की है? आपका जो "भारतीय खेल विकास प्राधिकरण" है, वह आज कटोरा लेकर बैंकों के पास और तमाम कंपनियों के पास घूमता रहता है, उसके पास बजट की व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि उसकी बिल्डिंग की सफाई और पुताई के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खेलों के लिए आपने 350 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो 'ऊँट के मुंह में जीरे' के समान है।

इंटरनेट की व्यवस्था करना एक अच्छा काम है, लेकिन आप गांव में जाकर पूछिए तो सही, लोग ट्यूबवेल पर या दूसरे गांव में जाकर अपना मोबाइल चार्ज करवाने के लिए रखवाते हैं। कई बार तो लोग उनकी बैट्री ही बदल लेते हैं। आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन आज तक गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम कैसे cashless भारत बनाएंगे? कैसे net banking की व्यवस्था करवाएंगे? अभी मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग करोड़ों-अरबों रुपया 'स्वच्छ भारत अभियान' पर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, रोज़गार नहीं है।

एक तरफ आप करोड़ों रुपया लगाकर यह सिखा रहे हैं कि आपको कहां पर शौच करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ATM-Paytm चलाओ। जिनके पास शौच जाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, वे ATM-Paytm कैसे चलाएंगे? इसके लिए पहले आपको उन्हें शिक्षित करना होगा, उनके लिए मकान की व्यवस्था करनी होगी, पढ़ाई का इंतजाम करना होगा, दवाई का इंतजाम करना होगा, तब जाकर वे किसान आपका ATM-Paytm यूज़ कर पाएंगे।

मान्यवर, पूरे देश में ...(व्यवधान)... जब आपका नम्बर आएगा, तब आप बोल लीजिएगा।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आप पहले सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा।...(व्यवधान)... आप बैठिए।...(व्यवधान)... उनको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : आपने पूरे देश में ग्रामीण बैंकों को खत्म करने का काम किया है। ग्रामीण बैंक गांवों की रीढ़ है, लेकिन हमारी केन्द्र की सरकार ने उनको खत्म करने का काम किया है। ग्रामीण बैंकों को उन्होंने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, इसलिए देश आज़ाद होने के बाद हर गांव में, हर न्याय पंचायत में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अब आपने पूरे देश में ग्रामीण बैंकों के शेयर प्राइवेट कर दिए, तो कैसे वे लोग net banking के माध्यम से आदान-प्रदान करेंगे? अब आप मज़दूरी का लेन-देन भी

बैंक के माध्यम से करेंगे। गांव में आपके पास बैंक है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो कैसे आप इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएंगे?

(2j/rpm पर जारी)

RPM-KR/2J/4.05

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : मान्यवर, आज देश में लोग परेशान हैं। हमने आपको बताया कि इन्हें ऋण की चिन्ता है कि ऋण देकर के हम बैंकों को और मजबूत कर देंगे, जिस तरह से इन्होंने नोटबन्दी कर के बैंकों को मज़बूत कर दिया और अब बैंक वाले मालामाल हो गए। आज हमारे पूरे बुन्देलखंड के किसान बरबाद हो गए हैं। आपने 15 लाख रुपए देश के प्रत्येक आदमी को देने का वादा किया था, लेकिन वे नहीं दिए, इसलिए हमने मांग की थी कि आप कम से कम बुंदेलखंड के किसानों का कर्ज़ा माफ कर देते या भले ही पूरे देश को नहीं, तो कम से कम बुन्देलखंड के किसानों को ही 15-15 लाख रुपए ही दे देते। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं।

मान्यवर, हम लोगों ने बजट में कई बार मांग की कि बुंदेलखंड की जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, उन्हें रेगुलराइज़ किया जाए। वहां से अनेक लोग रोजगार की तलाश में मुम्बई एवं अन्य बड़े नगरों को जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। वहां एक 'तुलसी एक्सप्रेस' चलती है। उसे प्रति दिन चलाने का काम कीजिए। इसी प्रकार 'रीवांचल एक्सप्रेस' है, जो बुंदेलखंड को जोड़ती है, वह कानपुर और इलाहाबाद से होकर न चले, बल्कि बांदा से चले। इसी प्रकार हमने अन्य अनेक

ट्रेनों के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा है, उन्हें बुन्देलखंड से जोड़ने का काम करें।

मान्यवर, सरकार का यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन और किसान-गरीब विरोधी है। इन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए औद्योगिक घरानों के माफ करने का काम किया है, लेकिन किसानों का एक रुपया भी माफ नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कहता हूं कि इसमें आप संशोधन करिए और उद्योगपतियों के बजाय गरीब के लिए काम कीजिए तथा इसमें गरीबों और किसानों को स्थान दीजिए, धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (WEST BENGAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. India's economy moves mainly on four wheels, that is, Government's spending, consumption, export and private investment. But this Budget focusses on the first two because the export has lost momentum. Even the FM has mentioned this but nothing has been said how this declining export situation can be combated; and the windfall from oil has gone into refurbishing the Government's finances, and good times may end, if food prices inch up. Indian companies are cash rich. They are not investing here or abroad. Bank credit off take is the lowest in

recent period and nothing has been said about the mounting NPAs over the years. Who are the big fishes who have eaten up the public money from the banks? Sir, this Budget Speech of the hon. Finance Minister is full of assurances, rhetoric and some jugglery of figures. First of all, I would like to read para 4 of the Budget Speech where the hon. Finance Minister has assured that we shall continue to undertake many more measures to ensure that the fruits of growth reach the farmers, the workers, the poor, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, etc., etc. Now we are tired of listening to the story of growth because as per the World Bank 's Report published in October, 2016, a few months back, India accounts for one in three of the people living below the international poverty line, and that way India is having the highest number of the poorest people in the world, among all the countries in the world.

Secondly, India's 224 million people live Below the Poverty Line. Second is Niegeria, 86 million among the world's population.

(Continued by2K/KS)

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (contd.): Sir, there is another country, Nigeria. Nigeria also has only 86 million compared to India's 224 million people living below the poverty line. Sir, 800 million Indians live on less than US $ 1.90 a day. What a shame! We are talking about growth rate, etc.!

Sir, according to Human Development Indicators in India, the country's wealth has increased -- no doubt, it has increased -- in the last two-and-a-half decades more than three times, from 75 trillion rupees to 224 trillion rupees. But the irony is that more than 60 per cent of this increase in wealth has gone only to the top one per cent of Indians. In other words, one per cent of our population has grabbed 90 trillion rupees in terms of the country's increase in wealth. This is the story of our growth. And here is a reflection of that story in the Budget Speech of the hon. Finance Minister that we are committed to the increase in growth for the poor, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, youth, etc.! Sir, if the growth rate does not reflect the financial conditions of the poorest of the poor people or the poorer sections of the people, then this growth rate shall continue to be a myth according to me, and I may be excused to say so.

Sir, I now come to para 7 of the Budget Speech. Here again, the hon. Finance Minister has claimed, and rightly so, that the Foreign Direct Investment has increased by 36 per cent. Foreign Direct Investment has increased by 36 per cent, but – this 'but' is very important – there is no mention of how much FII is going back from the share market. I have a figure, Sir. I would like to place this figure before you. FIIs were consistently selling both, in equity and fixed income markets, since November 8. Kindly remember the date. Since November 8, the FIIs have been consistently selling both, in equity and fixed income markets, and the net outflow of this is Rs. 42,000 crores in the debt market and Rs. 28,000 crores in the equity market, as on 23 January, 2017. Therefore, since November, 8, 2016, till January 23, 2017, Rs. 70,000 crores have already gone out. And the Finance Minister has not cared to speak a single word on this as to why this has happened, and what the policy of the Government is to combat such a situation in future too.

Sir, kindly move to para 11. Everyone has talked about it. This would be continued in all the public speeches. It is being talked about in the five States where elections are being held. And, thereafter also, it

would be referred to again and again. I am talking about demonetization. सर, मेरे विचार से यह भी एक जुमला है। पाँच राज्यों में जो चुनाव होने वाला था, यानी अब हो रहा है, तो नवम्बर में यह सोचा गया कि पाँच राज्यों में चुनाव होने वाला है, तब हमको तो लोग पकड़ेंगे कि तुमने बाहर से काला धन वापस लाने का जो आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ, हमारे खाते में 15 लाख जमा करने का आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ, तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? तो कोई ऐसा कदम उठाया जाए, कोई आंधी पैदा की जाए और चुनाव बीत जाने के बाद हम फिर अपना गीत-संगीत गाते रहेंगे और बोलेंगे कि वह तो चुनावी जुमला था।

(2एल/वीएनके पर जारी)

VNK-RSS/2L/4.15

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत) : मेरे विचार से यही एक कारण था कि उस समय अचानक यह कह दिया गया। हमारी नेता, सुश्री ममता बनर्जी हिन्दुस्तान की पहली लीडर हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया, फिर बाद में दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं ने भी बयान दिया। हम पर इल्जाम लगाया गया कि ये लोग तैयार नहीं थे।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

ये लोग तैयार नहीं थे, इसलिए ये लोग डर गए। मैं विस्तार से इसका मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ, यह सदन है, अपर हाउस है, लेकिन इसको हर

कोई समझता है। प्रधान मंत्री जी ने भी बोला कि ये लोग तैयार नहीं थे। इसका और भी एक अर्थ निकलता है। इसका मतलब यह है कि सत्ताधारी दल तैयार थे। ये लोग तैयार थे, ये लोग जानते थे कि क्या होने वाला है। ये लोग तैयार थे, जानते थे, इसलिए कोलकाता के बैंक में पैसा जमा हुआ, एक रात में हजारों करोड़ रुपए जमा हुआ। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, बिहार में पहले से ही कैश में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई, क्योंकि ये लोग तैयार थे। इन लोगों को इसकी जानकारी थी कि यह होने वाला है, इसलिए इनके पास जितना काला धन था, सब सफेद हो गया और जब तक ये सत्ता में रहेंगे, न कोई ईडी, न कोई सीडी, न कोई सीबीआई, न कोई एसएफआईओ कोई छानबीन करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, ये सब जानते हैं। दूसरे लोगों के पीछे इनको लगा देंगे, इसके पीछे लगा देंगे, उसके पीछे लगा देंगे। देरेक साहब ज्यादा बोल रहे हैं, देरेक साहब का थोड़ा कंठरोध करना है, इसलिए उनके ऊपर केस लगा दो, उनको जेल में भेज दो, ऐसा चल रहा है।

सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को जो प्रेस रिलीज निकाला था, 8 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है, ये दोनों मेरे पास हैं। शायद इसको सब लोगों ने देखा है। मैं इसकी दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ।

"With a view to curbing financing of terrorism through the proceeds of Fake Indian Currency Notes (FICN) and use of such funds for subversive activities such as espionage, smuggling of arms, drugs

and other contrabands into India, and for eliminating Black Money which casts a long shadow of parallel economy on our real economy, it has been decided to cancel the legal tender character of the High Denomination bank notes of Rs. 500 and Rs. 1000 denominations issued by RBI till now."

This is the objective of the Government Notification for demonetization. Some people say, demonization. I don't say so. Demonetization has four, five objectives. Black money comes at the last. The first one is, use of funds for subversive activities. My question is, after 90 days of the declaration of demonetization, how much fake currency has been seized? How much black money has been recovered? To what extent, have the subversive activities been curbed? Why is there no mention in the President's Address or the Budget speech or in any statement of the Government made so far? This House wants to know; the nation wants to know…. जनता तीन महीने से ज्यादा समय तक कतार में खड़ी रही, हिन्दुस्तान की सारी जनता तीन महीने से ज्यादा समय तक बैंक्स और एटीएम्स के सामने कतारों में खड़ी रही। वे इस उम्मीद में खड़े रहे कि हम आज जो कष्ट कर रहे हैं, शायद प्रधान मंत्री जी ने जो बोला, सरकार ने जो बोला कि सारा काला धन जब्त हो जाएगा, हिन्दुस्तान में

हरियाली छा जाएगी, इस आशा में हमारी जनता ने तीन महीने कष्ट सहन किया, जब कि अब उस जनता के सामने सरकार का कोई जवाब नहीं है। आज तक सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिये। उस जनता के सामने सरकार ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, एक लफ़्ज भी नहीं बोला कि कितना काला धन बरामद हुआ।

(2एम/एनकेआर-केजीजी पर जारी)

NKR-KGG/2M/4.20

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत) : कैसे कालाधन बरामद होगा? यह मात्र एक जुमला है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यह एक जुमला है। अगर जुमला नहीं होता, तो जैसा आपने बोला था कि हम विदेशों से कालाधन लाने का काम करेंगे लेकिन परसों हमारे वित्त मंत्री जी यहां एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि हमने सिंगापुर से एग्रीमेंट किया है, हमने मॉरिशस और साइप्रस से एग्रीमेंट किए हैं और न जाने कितने देशों के साथ एग्रीमेंट किए हैं। ऐसे एग्रीमेंट तो कई हुए। जैसे कोई एम.ओ.यू. होता है, दो देशों के बीच, उसके अंतर्गत एक साल में कितना investment वास्तव में आता है, उसे हम सब जानते हैं। वैसे ही एग्रीमेंट उन देशों के साथ हो रहे हैं, signature हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं? जब वित्त मंत्री जी ने बताया, उसे सुनकर लगा कि इस सरकार के आने के बाद यह काम शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे एग्रीमेंट हमारे कई देशों के साथ पहले से हो चुके हैं, 70 से ज्यादा देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं, जिनके अंतर्गत काले धन के बारे में वे हमें सारी information देंगे। स्विस बैंक इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चित है। जब

मैं छोटा था, उस समय से मैं सुनता आ रहा हूं कि स्विस बैंक में हिन्दुस्तान के कुछ लोग काला धन जमा करते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज भी सुन रहा हूं कि स्विस बैंक में ..(व्यवधान).. नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : नहीं, अभी बूढ़े नहीं हुए।..(व्यवधान)..

श्री सुखेन्दु शेखर राय : नहीं, पिछले 50 साल मेरे राजनीति में बीत चुके हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : सुनिए, अभी भी आप नौजवान हैं। ..(व्यवधान)..

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : चेयर का कहना है, तो मान लेना चाहिए। ..(व्यवधान).. चेयर की रूलिंग है, प्रश्न नहीं कर सकते। ..(व्यवधान)..We can't question the ruling of the Chair. The ruling of the Chair is that you are young.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: I bow to you. Now the question is स्विस बैंक की चर्चा पहले से शुरू हुई है। बहुत दिनों से हम स्विस बैंक के बारे में सुनते आ रहे हैं। विकीलीक्स ने एक लिस्ट निकाली, फिर सब चुप हो गए, शांत हो गए। अब कोई स्विस बैंक का नारा नहीं लगाता। जब उधर बैठते थे तो हर रोज नारा लगाते थे लेकिन आजकल चुप हो गए हैं। सवाल है कि क्यों चुप हो गए? स्विस बैंक के साथ हमारी डी.टी.ए. ट्रीटी अक्तूबर, 2011 में साइन हुई थी, जब यहां कांग्रेस सत्ता में थी। ये लोग नहीं थे। अक्तूबर, 2011 महीने में स्विस बैंक के साथ हमारी डी.टी.ए. ट्रीटी हुई। ये संत लोग हैं और आश्रम से आए हैं। ये संत

लोग पिछले ढाई सालों से क्या करते रहे? स्विट्जरलैंड से information लाकर इन्होंने सबको क्यों उपलब्ध नहीं कराई, यह सवाल आज पैदा होता है। यह संतों की सरकार है। यह भी जुमला है।

पनामा पेपर्स में बहुत रिपोर्टें आईं। इससे पहले वर्ष 2012 में, In February, 2012, no less a person than the CBI Director said that 500 billion US$ worth of Indians' monies are stashed outside the country and stored in different tax havens. And the experts say that a major portion of the money has been laundered back into India through foreign investments. एफ.डी.आई. हमारा बढ़ रहा है। यह टैक्स हैवन कहां है, इसे सब जानते हैं। लेकिन पनामा का नाम हमने पहले भी सुना था, एक सिगरेट का नाम था, जब कॉलेज में पनामा सिगरेट हम पीते थे। Sorry, I should not have uttered the word. Smoking is injurious to health. I correct myself. I think, that should be expunged! Cigarette portion should be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; 'Cigarette smoking is injurious to health' should be there.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: I stand corrected. Panama Island is a picturesque island, Sir; a beautiful island. लेकिन हिन्दुस्तान के बहुत से मान्यवर लोगों का पैसा वहां जमा है और यह सब अखबारों में आया है, जो

International transparency है, consortium of journalists है, उन्होंने निकाला है।

(DS/2N पर जारी)

DS-KLS/4.25/2N

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत) : उससे पता चलता है कि उसमें -- उन्होंने 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स निकाले और कहा जाता है कि उसमें 500 इंडियन नेशनल्स का नाम है, जिन्होंने फर्ज़ी एकाउंट्स खोलकर वहाँ पैसे जमा किए। उसमें हमारे बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेजिडेंट का भी नाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने गलत बोल दिया, तो मुझे इस बात की सज़ा दीजिएगा। उसमें बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेजिडेंट का भी नाम है। मुझे मालूम नहीं है कि वह लीगल रूप से गया या इल्लीगल रूप से गया, यह तो सरकार का काम है, जो इसकी छानबीन करेगी और इसको देखेगी।

श्री जयराम रमेश : छत्तीसगढ़ के सीएम के बेटे का नाम भी है। ...(व्यवधान)...

श्री सुखेन्दु शेखर राय : रमेश जी ने कुछ बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रमेश जी बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आदमियों का नाम है। क्या हुआ? जाँच क्यों नहीं हो रही है? तृणमूल के लीडर्स को पकड़ो और जेल में भेजो, ऐतराज़ नहीं, लेकिन संतों की सरकार, आश्रमाइट्स, आप लोग खामोश क्यों हैं? आप "पनामा पेपर्स" के बारे में कुछ तो कीजिए, कम से कम पूछताछ तो कीजिए! यह सब चल रहा है।

यह जो काले धन, काले धन, काले धन की आवाज़ उठाई गई, सिर्फ काले धन को पकड़ने के लिए demonetization किया गया, यह भी एक चुनावी जुमला है, इसलिए काले धन का एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ और न होगा, क्योंकि यह सरकार जानती है, यह भी मिली हुई है, मिलीभगत है। सर, यह जो demonetization का notification हुआ है -- यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसेल और हमारी कानूनी बिरादरी के लीडर, डा. अभिषेक मनु सिंघवी जी बैठे हुए हैं, ये शायद मुझ सपोर्ट करेंगे कि जो notification हुआ, उसमें बताया गया, 'In exercise of powers conferred under Section 26, Sub-section 2 of the RBI Act, 1934, the Government on the recommendation of the central bank, that is, Reserve Bank, has decided to declare the five hundred rupee notes and the one thousand rupee notes not to be legal tenders.' Fine, yes, the Government has the power to do that, nobody can challenge. The objective, nobody can challenge, the legal way the Government has issued a notification, nobody can challenge. Although some people have challenged it in the Supreme Court, I am not of that view. My view is that up to this, if I take on a plain reading of that provision, it is all right. But what had exactly happened? I have a newspaper, Sir, *the Indian Express*, if you kindly permit, I would read only a few lines from this newspaper of dated January 10, 2017. It says,

inter alia and I quote only two-three lines of the report submitted by the RBI to a Standing Committee of Parliament – it has been reported with quotations in this newspaper on the front page. "The Government on 7th November, 2016 advised the Reserve Bank that to mitigate the triple problems of counterfeiting, terrorists financing and black money, the Central Board of Reserve Bank may consider withdrawal of the legal tender status of notes of high denomination.' So, it was the directive from the Government to the Reserve Bank that you should discuss and decide and send the recommendation to the Government. But the Act says, 'no'. The provisions of the Act say that on the recommendation of the RBI, the Government may take the decision. यानी, पहले घोड़ा रहेगा, उसके पीछे गाड़ी रहेगी। घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रहेगी।

(2ओ/एसएसएस पर जारी)

SSS-MCM/2O/4.30

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (CONTD.): The cart cannot be placed before the horse. Here the RBI has been subjugated. It has acted on the dictates of the Government and the RBI did not have any planning, the RBI did not have any preparations. All of a sudden, it was

a bolt from the blue that the Government asked the RBI to send its recommendations. Provisions of the law do not say that, and the next day it was said that it was a surgical attack. It was a surgical attack on the RBI, surgical attack on the legal framework, surgical attack on the people of this country. And the hon. Supreme Court also remarked, observed, that it was not a surgical attack, it was 'carpet bombing', as a result of which not only 135 people died of shock and trauma but also millions of people, अभी वह जो चलता-फिरता मुर्दा है, वह workers informal sector का, plantations labourer, MSME में छोटे व्यापारी, सब बरबाद हो गए। हिन्दुस्तान की जो हमारी बुनियाद है, non-formal sector, उस बुनियादी ढांचे को हमने बरबाद कर दिया और गीत गा रहे हैं, बजट में संगीत गा रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जी। Demonetization के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि क्योंकि उनके सामने बोलने से मुझे उत्साह मिलता है।

बैंको से पैसा निकालने की लिमिट, सीलिंग भी लगा दी गई। हमारा बैंक एकाउंट है, सब का बैंक एकाउंट है। पहले बोला कि आप इतनी राशि निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। फिर धीरे-धीरे, करते-करते 24,000 रुपए कर दिए। इस बारे में उस नोटिफिकेशन में कोई उल्लेख नहीं है। अगर सरकार कोई कदम उठाती है या कोई सीलिंग होती है तो उसे नोटिफिकेशन में बताया जाता है। यह सरकार का दायित्व बनता है कि किस

कानून के कौन से प्रावधान के आधार पर यह सीलिंग इम्पोज़ की गई। उसमें इसका उल्लेख जरूर करना पड़ेगा। अगर उल्लेख नहीं करते हैं तो यह speaking notification नहीं है और इसलिए this non-speaking notification is expressly illegal, अब यहां वित्त मंत्री जी आ गए, वह तो हमारे हिन्दुस्तान के और बाहर देशों के लिए भी कानूनी हस्ती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कानून के आधार यह सीलिंग इम्पोज़ की गई, कोई कानून है तो उसका उल्लेख नोटिफिकेशन में क्यों नहीं किया गया? फिर उन्होंने बोला कि यह कानूनी सवाल है। दूसरी बात है कि परसों क्वेश्चन ऑवर में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में बताया कि 'that not for a single day had there been any shortage of cash.' यह सुनकर सारा हिन्दुस्तान चौंक पड़ा कि वित्त मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि एक दिन के लिए भी कोई करेंसी क्रंच नहीं था। इसका मतलब है कि बैंकों में पूरा पैसा था, ए0टी0एम0 में पूरा पैसा था, तो फिर क्यों हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ा? कतार में लगे जो 135 आदमी मर गए और वे अब कब्र में सोए हुए हैं, तो ऐसा सुनकर वे भी जाग जाएंगे कि वित्त मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि बैंकों में एक दिन के लिए भी करेंसी क्रंच नहीं था, बैंकों में सारा पैसा था, ए0टी0एम0 में सारा पैसा था।

(2P/SC पर जारी)

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत) : अभी चिदम्बरम जी बता रहे थे कि साउथ इंडिया में कितने सारे ATMs में आज भी पैसा नहीं है। वे कहते हैं, डिजिटल। बहुत अच्छा डिजिटल! उस समय हमारे ATMs खत्म हो गए, हमारे ATMs की ज़ुबान बंद हो गयी, लेकिन Paytm चालू हो गया। उस Paytm के पीछे अलीबाबा है और अलीबाबा के साथ चालीस चोर भी हैं। ATM चला गया और Paytm आ गया - उसने कितना पैसा कमाया, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोल रहा हूं। एक स्टैंडिंग कमेटी में आरबीआई के किसी अधिकारी ने बोला कि हमारे good friends बोल रहे थे कि अगर और पहले demonetization हो जाता तो हमारा और ज्यादा लाभ होता। He was on record saying that. यह अलीबाबा और चालीस चोर का किस्सा जाने कब सब लोगों को मालूम पड़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मालूम पड़ेगा, उस दिन इस संतों की सरकार का जो असली चेहरा है, वह सामने आ जाएगा। सर, जयललिता जी की एक हिन्दी फिल्म बनी थीं, वे गुज़र चुकी हैं, मैं उनकी बहुत इज्ज़त करता हूं। उस फिल्म का नाम था, "इज्ज़त" जिसमें धर्मेन्द्र जी हीरो थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : बहुत पुरानी फिल्म है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय : बहुत पुरानी है। उन्होंने एक ही हिन्दी फिल्म की थी, जो धर्मेन्द्र जी के साथ की थी। सन् 1970 उस फिल्म में मोहम्मद रफी जी का एक गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। गाने की दो लाइनें थीं :

"क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी सूरत छुपी रहे।

नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे।"

इस संतों की सरकार के लिए मोहम्मद रफी जी का वह गाना एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ..(व्यवधान).. मैं तो स्वीकार करता हूं कि आप संतों की सरकार हैं, मैं आपको दुश्मन नहीं कह रहा हूं, मैं तो संत कह रहा हूं। सर, पैरा - 13 में वित्त मंत्री जी ने एक कविता कही।

"इस मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप,

जो बात नई है, उसे अपनाइए आप।

डरते हैं नई राह पर चलने से क्यों,

हम आगे-आगे चलते हैं, आइए आप।"

वाह! क्या कविता सुनाई वित्त मंत्री जी ने! कविता सुनकर मुझे एक पुराने शेर की याद आयी and I quote,

"वह समझता है कि हर शख्स बदल जाता है,

उसे लगता है, ज़माना उसके जैसा है।"

सर, यह कविता कहना ठीक है, शेरो शायरी ठीक है, लेकिन बजट गवर्नमेंट का एक serious document है। आप देखिए कि पैरा -21 में उन्होंने क्या कहा? In para 21, he said, "In last year's Budget speech, I focussed on 'income security' of farmers to double their income in 5 years." पिछले

साल उन्होंने यह कहा था। सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक साल में डबल हुआ?

सामाजिक कार्य और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : पांच साल में कहा था।

श्री सुखेन्दु शेखर राय : पांच साल में कहा था, ठीक है, मैंने मंत्री जी की बात मान ली। उन्होंने पांच साल के लिए बोला था। आपने ठीक किया, मुझे सुधार दिया। सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणापत्र, Election Manifesto निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम किसानों का प्रॉफिट डबल कर देंगे। ढाई साल में वह कितना हुआ, कितना बढ़ा? कुछ तो आंकड़े दीजिए, सरकार की तरफ से कुछ तो statistics सदन में दीजिए, ताकि हम देखें कि सरकार अच्छा perform कर रही है और जो उन्होंने चुनावी assurance जनता को दिया था, उस assurance को वे पूरा कर रहे हैं। सब चुनावी जुमले हैं, क्या करें? सर, पैरा - 64-67 में "Health" के बारे में बताया गया है। It was said that the Union Budget shows an increase of 23 per cent in the allocation for healthcare. I congratulate the hon. Finance Minister for increasing the allocation for health to the extent of 23 per cent.

(Contd. By USY/2Q)

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (CONTD.): But, again, there is 'but'. 'But' is important. But these figures are quite deceptive. When you consider the overall picture, the budgetary increases have been shown against the figures of the previous year. You will notice that the Finance Minister had instituted an unprecedented curb of 13 per cent in the Budget allocations on Health in 2015-16. It shows the hollowness of this apparent increase. जैसे सेल होती है, स्टाक क्लियरेंस सेल होती है, सामान का दाम पहले 100 रुपया बढ़ा दिया, फिर मैंने 50 परसेंट डिस्काउंट बोला। इधर इसका उलटा हुआ। इधर दो साल से हैल्थ के बजट को घटाते गए, घटाते गए और इस बार 23 परसेंट इन्क्रीज करके बोल रहे हैं कि देखो, मैंने 23 परसेंट हैल्थ का बजट इन्क्रीज कर दिया, ऐसा हो रहा है। श्री तपन कुमार सेन ने बताया है कि यह adjustment of heads है।

Sir, paragraph 83 speaks about privatization of Railways. Tapan*da* will bear with me. It says that a new Metro Railway Act will be enacted which will facilitate greater private participation and investment in construction and operation. ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1861 में जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, तो उस समय सरकार के पास रेलवे नहीं थी। बहुत दिनों बाद 1924 में सरकार ने रेल कम्पनी को अपने हाथ में लिया। हमारे देश में मुम्बई से ठाणे तक रेल चलने का सिलसिला शुरू हुआ, बंगाल में भी शुरू हुआ। उस समय

सारी प्राइवेट कम्पनीज़ थीं, तो हमारी सरकार भी मेट्रो रेल से प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर रही है। रेल बजट तो छीन लिया, अब हम लोग प्रभु जी की कृपा से वंचित हो गए, अब हम सब को जेटली जी की कृपा से चलना पड़ेगा। रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसकी मेट्रो से धीरे-धीरे शुरुआत हो रही है और धीरे-धीरे सारी रेलवे प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, वही ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो 1861 में किया था, उसी जगह वह घड़ी को पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, सरकार का रवैया है, जनता सफर करे या न करे, चुनाव में देखना है। पहले तो यू0पी0 में देखेंगे, हालांकि वहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे।

Paragraph 184 deals with transparency in electoral funding. हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास डाक्युमेंट्री एविडेंस है, जब से हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पैदा हुई, जब से हम चुनाव लड़ रहे हैं, बीस साल से ज्यादा समय हो गया है, तब से हर चुनाव मेनिफेस्टों में हमारी यह मांग है कि करप्शन को हटाने के लिए सबसे बड़ा कदम होना चाहिए कि पोलिटकल पार्टीज़ को चुनाव में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। चुनाव में स्टेट फंडिंग हमारी मांग है। अब सरकार ने क्या किया, through the Election Commission, not through Government. The funding should be made through the Election Commission, which is a constitutional authority. यह हमारी मांग है। सरकार ने क्या किया, जो कैश की लिमिट 20,000 रुपये थे, उसको 2,000 रुपये कर दिया, जो लोग 19,000 रुपये दिखाते थे, वे अब 1,900 रुपये दिखाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, श्रम ज्यादा

लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। आप कहते हैं कि कोई भी बांड खरीदो, उसको आईडेंटिटी देनी पड़ेगी, उसको आई कार्ड देना पड़ेगा, उसको अपनी आईडेंटिटी बतानी पड़ेगी, तो कौन आपको फंड देने के लिए आएगा। इसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? कैश की लिमिट तो है, लेकिन कैश और चेक मिलाकर, कुल मिलाकर कोई तो अपर लिमिट होनी चाहिए कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी इतने से ज्यादा डोनेशन नहीं ले सकती है, कहां पर लिमिट है? इसका मतलब यह है कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लाती है, उसी तरह से जो बड़ी पार्टी सत्ता में है, इसका छोटी पार्टी को खाने का इरादा है। यह भी एक जुमला है। यह मद्देनजर रखते हुए कि यू0पी0 में चुनाव हैं, ये सब ऐलान बजट में कर दिया गया।

(HMS/2R पर जारी)

PK-HMS/2R/4.45

श्री सुखेन्दु शेखर राय (क्रमागत) : हम चाहते थे कि इस पर national debate हो, सरकार national debate invite करे। सरकार सब पार्टीज को बुलाए, public से opinion मांगे कि electoral reforms कैसे किए जाएं? सर, funding के अलावा और बहुत सी चीजें हैं। इस बारे में मेरा यही submission है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

मोदी जी के सफर का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी डेढ़ साल पहले शायद चाइना के शंघाई में सफर पर गए थे। वहां Indian

Diaspora की एक बहुत बड़ी मीटिंग arrange की गयी थी। उसे याद कर के बार-बार मेरे मन में एक गीत याद आ जाता है। यह गीत मुझे मोदी जी का वहां का भाषण सुनकर याद आता है। मोदी जी ने वहां भाषण में ये दो लाइनें बोली थीं -

"दुख भरे दिन बीते रे भइया,
अब सुख आयो रे।"

मोदी जी ने ये लाइन अपने भाषण में बोली थी, तो मुझे लगा कि ये मैंने कहीं सुना है। यह "मदर इंडिया" फिल्म का गाना है जोकि 1957 की फिल्म है। 60 साल पहले यह film release हुई थी और 60 साल बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री चीन में जाकर "मदर इंडिया" फिल्म का गाना गा रहे हैं, क्या सौभाग्य है हमारा? वह गीत मरहूम शकील बदायूंनी जी ने लिखा और उसमें संगीत मरहूम नौशाद जी ने दिया था। इसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे, शमशाद बेगम और आशा भोंसले वगैरह ने गाया था। सर, यह एक कोरस गाना था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can sing it.

श्री सुखेन्दु शेखर राय : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। तो उन दो लाइनों के बाद भी और लाइनें हैं, जिन्हें मोदी जी ने नहीं बोला। मैं शुरू से उसे दोहरा रहा हूं :

"दुख भरे दिन बीते रे भइया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे।"

उसके बाद के अंतरा में है -

"आज तो जी भर नाच रे पागल, कल न जाने रे क्या होय,
दुख भरे दिन बीते रे भइया, अब सुख आयो रे।"

तो प्रधान मंत्री जी को ये बाकी के लफ्ज मालूम हैं कि नहीं, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सत्ताधारी पक्ष के मंत्री जी और दूसरे लोग बैठे हैं जिनके साथ मोदी जी का बहुत अच्छा संपर्क है ..(व्यवधान).. रेन कोट तो ठीक है, वह उनका विचार है। मैं चाहूंगा कि "मदर इंडिया" के जिस गाने की उन्होंने चाइना में शुरुआत की है, वे उनको यह अंतरा सुना दें।

"आज तो जी भर नाच रे पागल, कल न जाने रे क्या होय
दुख भरे दिन बीते रे भइया, अब सुख आयो रे।"

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Sukhendu Sekhar Roy. Now, Shri Tapan Kumar Sen. I now want to take the sense of the House. ..(Interruptions).. Today, being the last working day of this week, I think, if you all agree, we will adjourn at 5.00 p.m.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, Mr. Tapan, you have only 10 minutes. If you don't want to speak, I will call Mr. Raja. Either you or Mr. Raja. Mr. Tapan, do you want to speak?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, you speak. But, at 5.00 p.m., we will adjourn. That is what has been agreed upon.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to give my observations on the Union Budget, 2017-18. From my Party, my other colleagues will be speaking on other aspects of the Budget. I will only throw light on the basic matters.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be only after one month.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes, they will speak then, Sir. But I will just focus on the basic macro aspect.

(Contd. by PB/2S)

PB/2S/4.50

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): I think, Mr. Chidambaram has done a great job by giving all the figures here. However bright the Budget might have been shown, the fact of the case is that the Budget is a contractionary Budget. And, I remember the first statement made by our present Finance Minister, Shri Arun Jaitley, in this House itself while talking about the financial position of the country that if our expenditure pattern is contractionary, it retards the growth. I think, the same thing Mr. Chidambaram has told today. As has been told, as a

percentage of GDP, it has declined from 13.4 to 12.7 per cent. And please take note of it. If all the three Budgets from 2014 onwards are seen, it is a consistent decline. That is what is called *jumla.* It is a consistent decline in figurative term. That is consistently contractionary. Expenditure is getting contractionary in terms of GDP, and this is reflected in other aspects, in social welfare aspects. In terms of figures, it is shown that a great increase has been made for SCs, STs, women, tribal population and minorities. But if you go in terms of GDP, it is hardly five per cent for the women who constitute 50 per cent of the population. It is 1.48 per cent for the SCs and some two per cent for the STs, if I remember the correct figure. It is not more than that. What is the percentage of this population in our country? Sir, the problem remains in the basics. So, whatever flowery language, ornamental language you may use in the Budget, that does not serve the purpose. That has been done to befool the people, and, in that sense, I call this an absolutely deceptive Budget.

Hon. Deputy Chairman, Sir, my second point is that it is about an important focus of this Government in managing its economy. That is disastrous for our country's national economy and self-reliance. They

are going ahead with privatization of all profit-making public sectors. Already, the NITI Aayog has made a list of 74 CPSUs. In my State, the three major industries, which are also heritage in nature, the Alloy Steel Plant of Durgapur, Bridge and Roof of Howarh**,** which is a running profit-making company, and also Bengal Chemicals, which was set up by Great Prafulla Chandra Ray, are being targeted to be privatized and closed down. …(Interruptions)… They are targeted to be closed down.

Two days back, I made a submission in Zero Hour. I repeat that. By targeting to wholesale privatization of our public sector network, which was the bulwark of our economic capacity, 'Make in India' slogan does not match with you**.** So, 'Make in India' slogan is being given to befool the people. Practically, the whole exercise of putting all our national assets to auction is aimed at serving, I repeat, the big foreign corporate and their *chamchas*, Indian *chamchas*. That is the main target of the entire privatization and economic exercise. For that, a dedicated agency was appointed in the name of NITI Aayog by dismantling our great tradition of Planning Commission which put in place, in a developing country like India, the concept of planning in economic development with an approach of an equitable growth

pattern. That Planning Commission has been buried. The NITI Aayog has replaced it, and they are appointed as a cheap marketeer of our public sector assets, even those public sector assets which are making profit and are adding to regular contribution to public exchequer.

My third point is on finance management, an important comment by hon. Finance Minister.

(Contd. by 2t/SKC)

SKC/2T/4.55

SHRI TAPAN KUMAR SEN (contd.): In his Budget Speech, he said, and I agree with him, that as far as payment of taxes is concerned, we are a non-compliant economy. It is there in his Budget statement. He has given figures in support of his statement. I fully agree with that statement of his. But what is he actually doing? He was applauded, but what is he doing about managing the finances? They are so concerned about the resource crunch. They even spoke eloquently about black money. What is black money? It is the earnings on which tax has not been paid. As per this year's Budget statement, this year, Rs. 6.59 lakh crore is the total amount of unpaid direct tax, corporate tax and income tax. It has accumulated over the years. It is increasing every year,

consistently. In the last three years, it has jumped from Rs. 4 lakh crore to Rs. 6.59 lakh crore. This was all unpaid income tax and corporate tax. The Government itself has admitted that out of this, on Rs. 81,406 crore, there is no dispute, but still, it is preferred that it remains uncollected. This is a deliberate promotion of pilferage from the national exchequer. It is the Government-pilferer nexus that is governing the country's economic management. I am sorry to say this, but this is the reality. On the other hand, in the present Budget, a further concession of Rs. 20,000 crore has been given to the direct tax account. I reiterate what Mr. Chidambaram has said, that the present situation warrants a sharp cut in the indirect tax load, so that people can purchase goods, create an effective demand in the market and create an atmosphere for investment. A concession of 20 per cent has been given on direct tax while they plan to collect an additional Rs. 75,000 crore as indirect tax through this Budget. Last year, it was an additional burden of Rs. 19,000 crore; the year before the last, it was Rs. 23,000 crore. In the first year, the concession given under direct and corporate tax was Rs. 8,000 crore. The same tax-thieves have been awarded with more concessions. Now, people cannot avoid

indirect taxes and so, you are imposing a burden on them. This is the so-called pro-poor approach of the Government.

Sir, my last point is about demonetization. Enough of drama has been done**.** Mr. Sukhendu Sekhar Roy just read out the four objectives. I don't go by TV speech; I go by the official statement made by the Government, or the Government notification, which Mr. Sukhendu Sekhar Roy read out just now. Now, what honesty, integrity and transparency demands is that this House must be told how much black money has been recovered. This House must be told how much counterfeit currency could be seized. This House must know the answer as to what extent the terrorist activities and terrorist funding could be contained. Almost hundred per cent of the money that has been demonetized has already come into the banking system. As per the RBI's statement dated the 2nd of January, it was 98 per cent. By now, it is almost 100 per cent. What does that mean? It means that all black money has been whitened and it is this Government that has facilitated the whitening of that black money. It was not automatic; it is not a mistake; it is an instrument by which whitening of black money has been facilitated. Corrupt people have been indulged. And, they are

talking about fighting against corruption! I think this is the biggest ever corrupt practice that has been indulged through this process of demonetization.

(FOLLOWED BY KSK/2U)

KSK/KLG/5.00/2U

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan Kumar Sen, you can continue your speech in the next part of the Session.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Okay, Sir, I will continue it in the next part of the Session.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, rarely have we seen any speaker speaking in this part of the Session and also continuing in the next part of the Session. Tapan*babu* gets that privilege.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is a special privilege. Now, we shall take up the Special Mentions. I can allow the Members to lay them on the Table, if they like.

SPECIAL MENTIONS*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ahamed Hassan - not present. Shri Tiruchi Siva.

RSS/9A/

DEMAND FOR TAKING STEPS TO GRANT STATUS OF WORLD HERITAGE SITE TO KALLANAI DAM ON RIVER CAUVERY IN TAMIL NADU

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir**,** the Grand Anicut, popularly known as the Kallanai dam, was built over 2000 years ago across the Cauvery river, near Tiruchirappalli, Tamil Nadu, by the Chola king, Karikalan, to divert the river to the delta districts, thereby boosting irrigation and loss of crops due to floods.

Seen as an engineering marvel, the dam is a marvellous piece of hydraulic structure built across the Cauvery river, in its sandy bed, in the lst century A.D., and is one of the oldest water regulating

---

* **Laid on the Table.**

structures in the world that continues to be functional. In fact, Sir Arthur Cotton's 19th century dam across Cooleron river, is said to be a replication of Kallanai.

Besides attracting a large number of tourists from across the world, the dam has fascinated historians and engineers alike. However, the technological importance and historical background of Kallanai are less known.

Point (iv) of the selection criteria used by UNESCO to declare a site as a World Heritage Site states that the site must be, "an outstanding example of a type of building, architectural, or technological ensemble or landscape which illustrates significant stages in human history."

An ancient site of historical importance, and a model for engineers all over the world, it would be fitting and proper to declare the Kallanai dam a World Heritage Site.

I would urge the Government to take all possible steps so as to grant the status of 'National Monument' to the Kallanai dam, such that it can be declared as a World Heritage Site. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ms. Dola Sen - not present. Shri Derek O'Brien.

KGG/9B

DEMAND FOR TAKING STEPS TO ENSURE PRIVACY AND SECURITY WHILE PROVIDING SERVICES ON BASIS OF AADHAAR DATABASE

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, over 50 websites and mobile applications have been shut down recently, which provided Aadhaar-related services illegally. These apps and websites provided unauthorized Aadhaar-related services like downloading the Aadhaar card, providing status of Aadhaar generation, PVC Aadhaar Card, etc., to users, and collected data about Aadhaar numbers and enrolment details.

The Unique Identification Authority of India stated that none of the owners of these apps or websites have been authorized to provide such services, or collect the data, and that their actions are illegal. The Government should name and list the culprits on a separate page, which users could share to avoid getting scammed and raise public awareness about such scams.

It has become increasingly important for the Government to secure the Aadhaar database as it is now being used all over the country. Last month, various private companies were asked not to allow merchants on their platforms to collect Aadhaar information from the general public for printing Aadhaar cards.

Earlier in January, 2017, the Government announced Aadhaar Pay which allows anyone to link their bank account with their Aadhaar number, to make and receive payments electronically. With the lack of privacy and data protection legislation, it is necessary to provide for security standards for collection and storage of Aadhaar data.

(Ends)

KLS/9-C

DEMAND FOR TAKING EFFECTIVE MEASURES TO CHECK INCIDENTS OF ONLINE TROLLING IN SOCIAL MEDIA

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, in the last few years a new phenomenon has gradually evolved in social media known as "Trolling". Trolling is when a person typically posts cynical, irrelevant remarks or off-topic messages in an online community. In recent past many journalists, celebrities, politicians and even common citizens have faced abuse, ugly comments for expressing their views online.

Women are the worst victim of trolling practices. In the world of "Photoshop", character assassination has become very easy. Death and rape threats online has become a common phenomenon and unfortunately one don't know where to complain.

Sir, I appreciate the fact that few months back an "anti-trolling body" was set up by hon. Minister for Women and Child Development to handle the complaints of trolling against women online. Hundreds of complaints were registered immediately but there is no awareness

about the number of cases resolved and also about the present status and the success of this body.

Sir, there is another serious concern related with trolling. It is said that we often categorize Journalists under the category of paid media but still consider paid trolls as urban myth. Trolling has become a much organized practice and is a tool used by political parties against their opponents.

Sir, without me, taking names, - recently a senior lady journalist wrote a book called "I am troll" highlighting how a particular political party has involved itself in organized trolling against all those who don't adhere with their ideology. Sir, this is a serious matter and needs immediate attention.

(Ends)

Shri ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA) : Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

(Followed by 9D/SSS)

SSS/9D

DEMAND FOR TAKING EFFECTIVE MEASURES TO MAKE COUNTRY POLIO FREE IN VIEW OF RETURN OF VACCINE DERIVED TYPE 2 POLIO VIRUS IN GUJARAT

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (KARNATAKA): Sir, it is a matter of grave concern that we see a return of Vaccine-Derived Type 2 Poliovirus, with the latest instance occurring in the state of Gujarat.

The World Health Organization called for India to transition from Trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV) to Bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV) by May 2016. The rationale is that 90 per cent of all vaccine-associated paralytic polio cases and 40 per cent of all circulating vaccine-derived poliovirus cases result from the type 2 component of tOPV. A sample collected from Ahmedabad tested positive for Vaccine-Derived Type 2 Poliovirus four months after India had officially ceased the use of tOPV. This is especially troubling since it indicates the potential re-emergence of Polio in our country which was declared polio-free in 2012.

The discovery of 2 vials of tOPV at a private vaccine retailer and 11 vials of tOPV at eight private clinics in Gujarat during the period of

September 14, 2016-October17, 2016 highlights the importance of ensuring that the private sector is made aware of the consequences arising from the continued usage of tOPV. Further, this also indicates that urgent steps taken towards the identification of continued usage of tOPV must carefully assess and regulate the private sector, especially those facilities that are not affiliated with an organised medical association. Given that the risk of type 2 virus evolving into a circulating vaccine-derived poliovirus increases over time, immediate concrete action must be taken to ensure that India's children remain free of the polio scourge. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Husain Dalwai - not present. Chaudhary Munvvar Saleem - not present. Dr. V. Maitreyan - not present. Shri T. Rathinavel.

NBR/9E

DEMAND FOR WITHHOLDING DECISION OF SHIFTING REGIONAL NEWS BULLETINS OF ALL INDIA RADIO, PARTICULARLY TAMIL, FROM NEW DELHI TO RESPECTIVE STATE CAPITALS

SHRI T. RATHINAVEL (TAMIL NADU): India reflects the concept of unity in diversity with its multicultural, multilingual population. As many

as 22 scheduled languages are recognised by the Eighth Schedule of the Constitution. It becomes utmost important to provide the citizen-centric news services in all the regional languages, including Tamil. The services thus offered need to be in one's mother tongue.

There is a circular from the Union Government regarding the shifting of national language bulletins of All India Radio from New Delhi to respective State capitals. In the first phase, Tamil, Malayalam, Assamese and Oriya are to be shifted. These national language bulletins are to be aired from the respective State RNUs from the 1st March 2017.

There were protests in the past when similar decision was taken. Unfortunately, the present Government too is trying to shift the Tamil News Unit from Delhi to Chennai. Since it is a national bulletin with a legacy of 78 years, it would be appropriate that it is aired from the national capital only. Otherwise, it will lose its national prominence.

There is an apprehension that this decision will kill all scope of balancing the regional language news bulletins with Hindi, English and

Urdu bulletins. This could also trigger a trend of lingual cleansing in the national capital, which hosts many language-related institutions like Akashwani.

I urge upon the Union Government to desist from shifting the regional news bulletins, particularly Tamil, from national capital to respective RNUs and expedite the implementation of national e-governance plan to ensure that the services and portals of the Union Government are provided in all languages recognised by the Constitution.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 9th March, 2017.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 9th March, 2017.